

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय, सांगानेर

पीठासीन अधिकारी:- श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 4/2018

निर्णय तिथि:- 04.01.2024

1. ग्यारसा पुत्र रामदेव जाति मालि निवासी- ग्राम सांगानेर जिला जयपुर (मृतक)
1/1 फूला पुत्री स्व० ग्यारसा पत्नी चौथू जाति माली निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/2 नौरती देवी पुत्र स्व० ग्यारसा पत्नी गोपाल जाति माली निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/3 मु० कानी देवी स्व० ग्यारसा जाति माली निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक)
2. हनुमान प्रसाद सैनी पुत्र स्व० श्री लच्छूराम सैनी जाति, माली, निवासी 17 बजरंग नर्सरी के पास, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर।
3. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री हनुमान प्रसाद सैनी जाति, माली, निवासी 17 बजरंग नर्सरी के पास, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर।

-वादीगण

बनाम

रामस्वरूप पुत्र कल्याण (फौत)

- 1/1 गोपी देवी पत्नी स्व० रामस्वरूप
 - 1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व० रामस्वरूप
 - 1/3 सीताराम पुत्र स्व० रामस्वरूप
 - 1/4 नवरत्न पुत्र स्व० रामस्वरूप
 - 1/5 कान्ता पुत्री स्व० रामस्वरूप
 - 1/5 उषा पुत्री स्व० रामस्वरूप
- जातियान माली निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. चन्दू पुत्र कल्याण
 3. रामनारायण पुत्र कल्याण
 4. जगदीश पुत्र कल्याण
 5. गुल्ली बेवा कल्याण
- जातियान माली निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 जा०दी०
निर्णय

वादी ने वाद पत्र बाबत वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 जा०दी० पेश हुआ। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि मूल वादी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ग्यारसा द्वांश हस्तगत वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकशर हके प्रस्तुत कर यह अभिव्यक्ति वर्णित किये है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता कल्याण आपस में रंगे भाई हैं। माम सामान्य स्थित भूमि मत खसरा नम्बर 539 व 532 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा एवं हाल खसरा नम्बर 3656, 3657 व 3658 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.39 हेक्टेयर भूमि पत्तकारान की पैतृक भूमि है, जिसमें वादी का 1/2 एवं प्रतिवादीगण के पिता कल्याण का 1/2 भाग है। लेकिन सीटिवमेंट ने बिना इच्छामार व बिना किसी सूचना के समस्त भूमि का इच्छा अकेले प्रतिवादीगण के पिता कल्याण के नाम अंकित कर दिया था, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण के पिता कल्याण ने अपने जीवनकाल में कभी नियत नहीं बिगाड़ी व नोनो भाईयो का अधिकार मानते हुए उसने वादी के हक में एक लेख दिनांक 08 अगस्त 1972 ईसवी को लिख दिया था। इसके अलावा पूर्व में महकमा अर्बन शीलिंग में भी इस भूमि को पैतृक होने के वारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता कल्याण को भूट दी है व कल्याण व ग्यारसा की समान अधिकार माना है। वादी ने अंत में यह अनुतोष माहा कि विनादित भूमि में उसको 1/2 हिस्से का स्वतन्त्र कार्तकार घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र में जिस लेखपत्र दिनांकित 08 अगस्त 1972 का हवाला दिया गया है, वह लेख पत्र ना होकर एक इकरारनामा है, जो कि पी डब्ल्यू-4 फूला देवी द्वारा अपनी साक्ष्य में बत्ौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी-2 पदांशित करवाया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह दस्तावेज लेख पत्र ना होकर एक विक्रय इकरारनामा है, जिसमें वादी ने उक्त भूमि 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता कल्याण द्वारा 999/- रूपये में विक्रय किया अंकित किया है। उक्त लेखपत्र / इकरारनामा दिनांक 08 अगस्त 1972 ही एकमात्र दस्तावेज है, जिसके आधार पर वादीगण अपने हक में 1/2 हिस्से की घोषणा का अनुतोष श्रीमान न्यायालय से मांग रहे हैं। राजस्थान कार्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में यह स्पष्ट वर्णित है कि इकरारनामों के आधार पर कोई घोषणा का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इकरारनामों के आधार पर वाद मात्र दीवानी न्यायालय के समक्ष ही किया जा सकता है तथा धारा 207 के तहत ऐसे वाद हेतु राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्णित है। उक्त कथों को माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी कई न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया है। इस प्रकार वादीगण का वाद-पत्र विधि द्वारा वर्णित एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र में स्पष्ट अभिव्यक्ति वर्णित नहीं किये है तथा क्लेवर ड्राफिटिंग करते हुए इकरारनामों को वाद-पत्र में लेखपत्र अंकित किया है ताकि इस आधार पर वाद खारिज ना हो। लेकिन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय द्वारा वाद पत्र के साथ ही वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन भी किया जा सकता है। प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह एक लेखपत्र ना होकर एक इकरारनामा है। आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रार्थना पत्र किसी भी स्टेज पर यदि इजराय की स्टेज पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके अलावा स्वयं न्यायालय भी उक्त बिन्दु को किसी भी स्तर पर निस्तारित कर सकती है। क्षेत्राधिकार के आभाव में न्यायालय द्वारा पारित डिक्ली भी प्रार्थना प्रामाण्य ही कानूनन मानी जाती है। इस प्रकार हस्तगत वाद Frivolous Suit की श्रेणी में आता है, जिसमें अंततः भी वादी को किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। वादी द्वारा हस्तगत वाद सन् 1994 से ही चला रखा है तथा



उपखण्ड अधिकारी
जबपुर, दिल्ली (सफि-3)

प्रतिवादीगण को अनाकरण ही हैरान व परेशान किया है, जिस हेतु भी प्रतिवादीगण विशेष हर्जे पेटे वादीगण से 10,000/- रुपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा वादीगण का हस्तगत वाद विधि द्वारा अहित एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपटित द्वारा 151 जाप्ता दिवानी का पेश हुआ। जिसका शूधम वृत्तान्त इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे के माध्यम से प्रार्थना पत्र में अंकित समस्ता आपत्तियों न्यायालय के समक्ष उठाई है जिसके सम्बन्ध में न्यायालय ने विवाधक विरचित किये गये है तथा प्रकरण में वादी साक्ष्य भी पूर्व हो चुकी है परन्तु प्रतिवादीगण साक्ष्य में विलम्ब करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी/वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जाप्त दीवानी पेश किया है विधि अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी निस्तारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 निस्तारित किया जाना आज्ञात्मक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षों अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि वादी घोषणा जवाब पेश किया है ग्यारसा व कल्याण रिश्ते में भाई है। विवादित भूमि पैतृक है। जिसमें ग्यारसा का 1/2 हिस्सा व कल्याण का 1/2 हिस्सा है सेटलमेन्ट के समय अकेले कल्याण के नाम गलत कर दी है। दिनांक 08.08.1972 का लेख उभयपक्ष की सहमति बताई गयी है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी हेतु दावा का अवलोकन किया जावे। ऐसे दावे इकरारनामा के आधार पर घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। यद्यपि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी साक्ष्य पर पेश की है उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है। बोगस दावा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार की जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की है:-

1. मननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर अपील डिक्री 12603/04 (दौसा) जगदशी नारायण बनाम राधेश्याम निर्णय दिनांक 14.01.2009 आर0बी0जे0 (16) 2009
2. मननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निर्णय दिनांक 05.03.1992 हरीश चन्द बनाम राजाराम आर0बी0डी0 (421) 1992
3. मननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निर्णय दिनांक 22.09.1987 चौथू बनाम श्रीमती कस्तूरी आर0आर0डी0 1987
4. ए.आई.आर. 1954 एस.सी. पेज 340 वी.01.41 सी.एन. 82 from patna 14 april 1954 करणसिंह व अन्य बनाम चमन पासवान

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांबानेव)

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आर.आर.डी. 1975 दुर्गादान बनाम देवीदान निर्णय दिनांक 10.06.1974

अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण दावे में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेण्डिंग है। पहले निर्णित किया। इतने समय बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश की गई है। दोनो लेख पत्र व नक्शा पेश किया उसके आधार पर काबिज है इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय की आर.एल.आर. 1993(2) पेज 472 अरूण कुमार सैनी बनाम श्रीमती रामदुलारी व अन्य पेश की है।

पत्रावली दावा, राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अप्रार्थी का जवाब आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आधोपान्त अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस का सगौर मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वादी ने वाद पत्र में इकरारनामा दिनांक 08.08.1972 के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। किसी भूमि के बाबत् उसे खरीदने के इकरार मात्र से खरीददार भूमि का खातेदार नहीं बन सकता क्योंकि उक्त इकरारनामे के पश्चात् यदि राजस्व विक्रय पत्र (बयान) एक्जेक्यूट नहीं हुआ हो तो खरीददार उक्त इकरारनामे के आधार पर इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इकरारनामें के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं है। लेकिन केवल इकरारनामें के आधार पर न तो खरीददार का नाम अन्य प्रक्रिया द्वारा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो सकता है और न ही उसे उक्त भूमि को आगे बेचान करने का अधिकार है इसलिए इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये दावा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का दावा बाबत् घोषणा आराजीगत खसरा नम्बर 530 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 3658 रकबा 0.11 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर को खारिज किया जाता है इसी अनुरूप पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।



(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर (सांगानेर)

जयपुर